

an>

Title: Issue regarding decision to close units of Government of India Press in the country.

श्रीमती अर्पिता घोषे (बालूरघाट) : स्पीकर मैडम, मैं गवर्मेंट ऑफ इण्डिया प्रेस के बारे में एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ। गवर्मेंट ऑफ इण्डिया प्रेस के 17 यूनिट्स पूरे देश में हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में उसके पांच यूनिट्स हैं। अभी हाल ही में 20 सितंबर को कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है कि इसको वाइंड-अप करेंगे और पांच पर ले कर आएं, जिसमें से बंगाल में एक ही बचेगा। यह जो वाइंडिंग-अप ऑफ जीआई प्रेस है, इसकी पहले भी बहुत दफा बात हुई थी। जब ममता बनर्जी जी ने यहां पर एम.पी. थीं, तब मिड 1980 में उन्होंने इसके बारे में विरोध किया था, तब यह मामला बंद हुआ था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर सन् 2016 में 12वीं रिपोर्ट दी है कि अगर इसका एडवांस मॉडर्नाइज़ इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया जाए, एडवांस कंटेम्पेरी मशीनरी लाई जाएं और एसेशियल मैनपॉवर दिया जाए तो इसको मॉडर्नाइज़ कर के चला सकते हैं। ये 17 पूरे के पूरे चल सकते हैं। आपके माध्यम से सरकार से मेरी विनती है कि इस पर दोबारा विचार किया जाए और जीआई प्रेस को चलाया जाए ताकि हमारी यह गवर्मेंट ऑफ इण्डिया प्रेस रहे और जो लोग इसमें काम करते हैं उनकी भी लाइवलीहुड सही रहे।

माननीय अध्यक्ष :

कुँवर पुणेपेद्र सिंह चन्देल को श्रीमती अर्पिता घोषे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।